‘भारत के राजनीतिक बंदी हमारे बंदी हैं
- भारत के शहीद हमारे शहीद हैं’

राजनीतिक बंदियों के समर्थन में एकजुटता व संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

पूरी दुनिया में मनाया गया!

JAN SANGRAM PUBLICATION

भारत के जनयुध्द के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कमेटी (आईसीएसपीडब्बलू) के आव्हान पर पूरी दुनिया में भारत के राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई व उनको जेलों में दी जा रही अमानीवय यातनाओं के खिलाफ 25 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया. दुनिया की प्रगतिशील, जनवादी, माओवादी, क्रांतिकारी ताकतों ने भारत को 'जनसंघर्षों के जेलखाने' के तौर पर चिन्हित करते हुए भारत के शासक वर्गों द्वारा जनआंदोलनों के दमन के लिए चलाए जा रहे बर्बर व हिंसक आपरेशन ग्रीनहंट का विरोध किया और भारत सरकार से मांग की कि तुरंत क्रांतिकारी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा किया जाये. इस दिवस को मनाने से पहले कई देशों में जोरों से प्रचार अभियान भी चला.

हम उन कामरेडों के पक्ष में हैं जो क्रांतिकारी जनयुध्द का दिल बनी हुई हैं!

बिना शर्त तमाम राजनीतिक बंदियों को रिहा करो!

सर्वहारा क्रांतिकारी नारीवादी आंदोलन - इंटली की स्टेटमेंट

कहने को तो भारत 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' है लेकिन वहां की सरकार, सशस्त्र बल और सांसद महिलाओं के उपर रेप को जनता के उपर युध्द को बर्बर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं. भारत के ज्यादातर इलाकों में, शहरों में और खासतौर से उन इलाकों में जहां जनयुध्द चल रहा है महिलाओं के साथ सशस्त्र बलों द्वारा बलात्कार, हत्याएं आम बात बनी हुई है. इतना ही नहीं जब महिलाएं पुलिस की हिरासत में होती है तब भी उनको यातनाएं दी जाती हैं.

लेकिन महिलाएं अब क्रांति की तरफ मुड़ रही हैं, बलात्कार उन्हें विद्रोही बना रहा है, वे आज क्रांतिकारी जनयुध्द में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

भारतीय प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी राज्य दरअसल महिलाओं की जनयुध्द में व्यापक भागीदारी से डरा हुआ है और वह किसी भी कीमत पर इस भागीदारी को रोकना चहता है.

बहुत सारी बहादुर व दृढ़ महिलाएं आज बंदी हैं, उनकी हालात आज बुरी है, जेलरों द्वारा हिंसा व बलात्कार किये जाते हैं.

आयरलेंड की राजधानी दुबलायन में भारतीय दुतावास के बाहर प्रदर्शन का आयोजन

भारतीय दुतावास के बाहर आयरिश रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिक नेटवर्क फॉर यूनिटी, 1916 सोसाइटी, रिपब्लिकन सिन्न फिन, द दुबलायन इंटरनमेंट कमेटी सहित जनवादी, साम्राज्यवाद विरोध व माओवादी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ व राजनीतिक बंदियों के समर्थन में एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया.

उन्होंने भारतीय दुतावास को आयरिश जनता की तरफ से एक मांगपत्र भी सौंपा जिसमें भारत सरकार से मांग की गयी थी कि आपरेशन ग्रीनहंट को तुरंत बंद किया जाये, जनता पर दमन बंद किया जाये और तुरंत राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाये. भारत के माओवादियों के समर्थन में आयरिश जनता ने बैनर, झंडे उठा कर एकजुटता का प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शहीदों को श्रधांजलि अर्पित करते हुए कामरेडाना एकजुटता का प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाइचारा संबंधों की इज्जत करते हैं और हर संघर्ष में साथ खड़े हैं.

उन्होंने इच्छा जताई कि उनके इस प्रदर्शन की खबर भारतीय कामरेडों तक भी पहुंचेगी. और पता चलेगा कि आयरलैंड की जनता भी उनका समर्थन करती है.

भारत सरकार को आयरलेंड की जनता द्वारा लिखा गये पत्र के अंश

... जानबूझ कर व बर्बरता के साथ आपकी सरकार निर्दोष भारतीय मेहतकशों पर दमन चला रही है. हम मांग करते हैं कि तुरंत आपरेशन ग्रीनहंट को बंद किया जाये.

हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पर भारत की सरकार द्वारा जारी युध्द तुरंत बंद किया जाये और भारत का सैनिककीकरण रोका जाये.

हम सरकार से मांग करते हैं कि एपसफा, यूएपीए को रदद् किया जाये और तुंरत राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाये.

आपके सुंदर देश के प्राकृतिक संसाधन आपकी जनता के हैं, न कि विदेशी कार्पोट कंपनियों के. और जो उन संसाधनों की जनता के लिए रक्षा कर रहे हैं उनको आपकी सरकार सम्मान करने की बजाये जेलों में ठूस रही है.

आयरलैंड की जनता इस अमानीवय दमन को इजाजत नहीं दे सकती. आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की ठीक से देखभाल की जाये.

लाल सलाम...

ब्राजील

ब्राजील कम्युनिस्ट पुनर्गठन यूनियन (सीआरयूबी) ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारत के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की. और भारत के तमाम क्रांतिकारियों, जनवादियों के प्रति समर्थन व बिनाशर्त एकजुटता की घोषणा की. उनका कहना था कि भारत की पूराना सामंती राज्य क्रांतिकारियों व जनवादियों को जेलों में ठूस रहा है. खासतौर से सीपीआई माओवादी के कार्यकर्ताओं को जो 1967 से भारतीय सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं.

मणीपुर

मणीपुर के रिक्शा चालकों व दुकानदारों ने काले झंडे लहरा कर व काले बैज लगाकर भारतीय सरकार का विरोध किया व राजनीतिक बंदियों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया.

यूएसए - एनसीपी (ओसी) द्वारा जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति

भारत के राजनीतिक कैदियों के समर्थन में आइसीएसपीडब्लू द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय आव्हान का हमारा संगठन पूरी तरह से समर्थन करता है. हमारे संगठन का मानना है कि भारत के अंदर चल रहा युध्द दुनिया के पैमाने पर साम्राज्यवाद व क्राति के बीच जारी संघर्ष का मुख्य बिंदू है. और जो पार्टी इस युध्द का नेतृत्व एक अगवा दस्ते के रुप में कर रही है वह मार्क्सवाद के तीसरे चरण के रुप में माओवाद व सर्वहारा के वैश्विक सिध्दांत को लागू कर रही है.

यहां अमेरिका में, यहां भी बहुत सारे राजनीतिक बंदी हैं, जिनमें कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी और राष्ट्र मुक्ति योध्दा शामिल हैं, वह भी साम्राज्यवादी राज्य द्वारा आमानीवय यातनाओं का सामना कर रहे हैं.

हम साम्राज्यवादी केंद्र के कम्युनिस्टों के तौर पर भारतीय कामरेडों का पुरजोर समर्थन करते हैं जो भारतीय प्रतिक्रांतिकारी राज्य द्वारा अमानीय यातनाएं सह रहे हैं और उन हजारों शहीदों को श्रधांजलि अर्पित करते हैं जो वर्ग दुश्मन द्वारा लड़ाई या झूठी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं.

अमेरीकी साम्राज्यवादी राज्य भारतीय प्रतिक्रांतिकारी सरकार की पूरी पूरी मदद कर रहा है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी को कुचला जा सके. हम आपके बहादुराना त्याग व बलिदानों से प्रेरणा लेते हुए कार्य करते रहेंगे और लगातार भारतीय कामरेडों का रणनीतिक समर्थन करते रहेंगे.

स्पेन

Gran Marcha Hacia el counismo (साम्यवाद की ओर लांग मार्च) नामक ब्लॉग ने आइसीएसपीडब्लू के आव्हान का खुलकर प्रचार किया और भारतीय राजनीतिक बंदियों की दुर्दशा व अमानीवय परिस्थितिया के खिलाफ जनता को जागरुक किया. ब्लॉग ने लिखा कि भारत को दुनिया के बड़े लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाता है लेकिन वहां पर राजनीतिक बंदियों से पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है.

20 से 25 जनवरी के बीच इस मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी ब्लॉग ने अलग-अलग भाषाओं से सामग्री को अनुवाद करके अपने ब्लॉग पर छापा. इसने

भारतीय जेलों की अमानीवय परिस्थितियों, जेलों में राजनीति महिला-पुरुष बंदियों की हालात व उनके संघर्ष पर ध्यान केंद्रीत किया.

पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा संपर्क आइसीएसपीडब्बलू के ब्लॉग पर दुनिया की राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, ट्रेड यूनियनों, क्रांतिकारी मीडिया व अन्य प्रगतिशील ताकतनों द्वारा किया गया. न केवल स्पेन बल्कि योरोपीयन, लेटिन अमेरीकन, एशिया व उत्तर अफ्रीका के देशों ने भी भारत के राजनीतिक बंदियों के समर्थन में आवाज उठाई. एक दर्जन से ज्यादा वेबसाइटों/ब्लॉगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय

दिवस का जोरशोर के साथ प्रचार किया.

इटली

इटली में एक राष्ट्र व्यापी अभियान भारत के राजनीतिक बंदियों के समर्थन में छेड़ा गया. इसके तहत पर्चे, पोस्टरों, बैनरों से रोम, पालेरमो, मिलान, बेरगामो, टरांटो, बोलोगना, बेरेसीकीया, रेवेन्ना आदि शहरों में प्रचार किया गया.

रोम में छात्रों ने विश्वविद्यालय के बहार बैनर, पोस्टरों को लगा दिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रैस कार्यलय के बहार एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया.

पालेरमो शहार में 7 जनवरी को अभियान के शुभारंभ की मीटिंग की गयी. 23 जनवरी को सामूहिक चंदा जमा कर रात्रिभोज का आयोजन कर सामूहिक रुप से माओवादी आंदोलन पर बनी फिल्म को देखा गया. 25 जनवरी को गलियों में प्रदर्शन का आयोजन किया गया.

टरांटो - 28 जनवरी को फिल्म चक्रव्यूह देखी गयी, उसके जरिये व्यापक जनता में प्रचार किया गया, देश की बड़ी फैक्टरियों व कारखानों में पोस्टर, बैनर लगाए गये.

ब्रेसीकिया

19 जनवरी को दक्षिण एशीयाई व फिलिपंस के मजदूरों से एक आमसभा का अयोजन किया गया.

26 जनवरी को एक सभा का आयोजन कर चर्चा व अध्ययन किया गयाऽ

जर्मनी

22 जनवरी को सामूहिक रुप से चक्रव्यूह फिल्म देखी गयी और 25 जनवरी को एक बजे से 2 बजे तक आमसभा का आयोजन किया गया.

फ्रांस, श्रीलंका में भी पर्चे और पोस्टर बांटे गए, वहीं श्रीलंका में सिंगली भाषा में भाकपा (माओवादी) के महासचिव कामरेड गणपति के हमंबर्ग सम्मेलन के संदेश को अनुवाद कर बांटा गया.

आस्ट्रीया

आस्ट्रीया - में भी एक आमसभा का आयोजन किया गया.

दुश्मन की मांद : जेलों में
जनयुद्ध का परचम लहरा रहे
तमाम कामरेडों को जन संग्राम का लाल सलाम
भारतीय जेलों में राजनीतिक बंदियों के गूंजते नारे

6 दिसं 2013 को जेलों में बंद राजनीतिक बंदियों के आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का आव्हान किया गया था. जिसके प्रचार का असर 25 जनवरी से पहले ही जेल के बंदियों पर दिखने लगा. अलग-अलग जेलों में बंद कामरेडों ने जेल की अमानवीय यातनाओं व हालातों के खिलाफ भूखहड़तालों का सिलसिला जारी कार दिया. 26 जनवरी के बाद से अब भी जारी है. दुश्मन के सामने दृढ़तापूर्वक जनयुध्द का परचम लहरा रहे तमाम कामरेडों, प्यारे नेताओं को जन संग्राम लाल सलाम पेश करती है और आव्हान करती है कि फासीवादी राज्य के खिलाफ उसकी मांद में ही शहीदों को याद करते हुए संग्राम जारी रखें. हम जनता से व राजनीतिक कैदियों के परिजनों से, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि उनकी बिना शर्त रिहाई व जेलों में मानवीय हालातों को बनावाने के लिए संघर्ष को तेज करें.

17 जनवरी को झारखंड के हजारीबाग जिला की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल में 200 महिला-पुरुषों ने अपनी मांगों को लेकर भूखहड़ताल का आयोजन किया. उनकी मांग थी कि उन 31 कैदियों को रिहा किया जाये जो बरसों पहले अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा जानबूझ कर उनको वहां रखा जा रहा है. इससे पहले भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड नारायण सान्याल, रवि शर्मा और नारायण रेड्डी के नेतृत्व में 1300 कैदियों ने जेल में आंदोलन किया था. जेल के अंदर उन्होंने धरना दिया जिसमें तमाम कैदियों ने भाग लिया और जेल प्रशासन के खिलाफ जेल कें अदंर नारेबाजी

की. उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वह फिर 30 जनवरी से भूखहड़ताल पर चले जायंगे.

लेकिन फासीवादी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया इस कारण से मजबूरन फिर हमारे कामरेडों को 30 जनवरी से भूखहड़ताल पर जाना पड़ा. यह समाचार लिखे जाने तक उनकी भूखहड़ताल को पांचवा दिन पहुंच चुका था. करीब 100 कैदी लगातार भुखहड़ताल कर रहे हैं.

जेल प्रशासन के अनुसार महाराष्ट्र की नागपुर जेल में 169 कैदियों ने 30 जनवरी भूखहड़ताल शुरु कर दी है. हालांकि मानवाधिकार वकीलों का कहना है कि हर रोज 200 कैदी भूखहड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं. और हर रोज यह हड़ताल जारी है.

इधर हमारे राज्य ओड़िशा बहरमपुर सरकिल जेल के कैदियों ने भी 30 जनवरी को भूखहड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया. उनकी मांग है कि कैदियों सीधे कोर्ट में पेश किया जाये और उनकी सुनवाई नियमित की जाये. कैदियों को विडियों कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल किया जाता है, जहां वह अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते न ही अपने उपर लगे आरोपों पर बहस कर पाते.

भारतीय जेलों में 3 लाख ऐसे कैदी हैं जिनको सजा नहीं सुनाई गयी हैं और जेलों में सड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं है, या उनके परिजनों की हालत बहुत गरीब है जो महंगी कोर्ट कार्रवाइयों में भाग नहीं ले पाते. और खास बात यह है कि यह सब कैदी गरीब वर्ग से संबंध रखते हैं. झारखंड की जेलों में 135 ऐसे लोग हैं जो अपनी 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन सरकार उनको अभी भी रिहा नहीं कर रही.

वहीं सितंबर में झूठे केस में अरेस्ट किये गए राजनीतिक कैदी प्रशांत राही ने भी जेल से एक पत्र लिख कर अपने उपर हुई यातनाओं को उजागर किया है और बुध्दिजीवियों से अपील की है कि काले कानून यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाई जाये जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को फासया गया है. यूपीए ऐसा काला कानून है जिसमें शक के आधार पर, या माओवादियों को मदद करने के आरोप लगकर जेलों में ठूसा जाता है. इस के अंदर जमानत का भी प्रावधान नहीं है. यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, रौल्टएक्ट की नकल है जो उनकी संतान काले अंग्रेजों द्वारा जारी है.

महाराष्ट्र जेल में जेल बंदियों की तरफ से एक पत्र मिडिया को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नागपुर जेल में 7 महिलाओं साहित 177 कैदी है जिन पर माओवादी समर्थक होने का या माओवादी होने का आरोप लगाकर यूपीए, मकोका व मर्डर केश लगाकार गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने लिखा है कि हम बिना सजा पाये ही जेल काट रहे हैं.

उनहेंने जनता, बुध्दिजीविया, जनवादी अधिकार समुहों, कानूनी कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आपकी सक्रिय मदद व संघर्ष के बिना हमारा संघर्ष अधूरा है. आपसे अपील है. उनका आव्हान है कि आप सब हमारे संघर्ष का समर्थन करें.

ब्राजिल में प्रदर्शनकारी

पोलेरमो शहर में प्रदर्शनकारी

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद

दुनिया के मजदूरो एक हो !

JAN SANGRAM PUBLICATION